

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र



संदेश

एस.के. हालदार अध्यक्ष

पिछले वर्ष, केंद्रीय जल आयोग, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता से "सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता" (एसआईएमपी) शुरू किया है। यह सिंचाई जल उपयोग दक्षता तथा फसल जल उत्पादकता को सुधारने हेतु भारत में वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का प्रस्ताव रखता है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि कुछ परियोजनाओं की प्राथमिकता अनुसार तैयार किया जाये जिनका सबसे पहले आधुनिकीकरण किया जा सके। राज्यों ने गहरी रूचि दिखाई और केंद्रीय जल आयोग को विभिन्न परियोजनाएँ भेजी। एशियाई विकास बैंक तथा राज्यों के परामर्श से केंद्रीय जल आयोग द्वारा इन परियोजनाओं की जांच की जा रही है और उन्हें श्रेणीबद्ध किया जा रहा है। राज्यों के साथ विभिन्न विस्तृत परामर्श/सलाहकार बैठकें आयोजित की गई

और ये आगे भी जारी रहेंगी।

कार्यक्रम के दूसरे चरण के दौरान, भारत-यूरोप जल साझेदारी के विभिन्न विषय स्तम्भ की योजना बनाने में और उनके कार्यान्वयन में केंद्रीय जल आयोग ने सजग योगदान दिया है। इस भागीदारी के विषय स्तम्भ अधिकतर उन महत्वपूर्ण समस्याओं से संबन्धित है जिनसे जल-क्षेत्र जूझ रहे हैं जैसे-पर्यावरणीय बहाव, सिंचाई जल उपयोग दक्षता, नदी बेसिन प्रबंधन आदि।

केंद्रीय जल आयोग ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत राष्ट्रीय महत्व के 191 जलाशयों का तलछट सर्वेक्षण की योजना बनाई है। अध्ययन का प्रथम चरण पहले ही फरवरी, 2021 में शुरू हो चुका है जिसमें 32 जलाशय राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार राज्यों से लिए गए हैं। इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 17 अरब घन मीटर है। कार्य की प्रगति पर सतर्कता से निगरानी रखी जा रही है।

भारत के जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर हमारे प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, एनडब्ल्यूए, पुणे ने दिनांक 07.06.2021 से 23.08.2021 तक एक महत्वपूर्ण वेबिनार सीरीज़ करने की योजना बनाई है। यह कार्यक्रम निशुल्क होगा और उन पेशेवरों के लिए काफी लाभदायी होगा जो इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। इच्छुक प्रतिभागी जल प्रबंधन के इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में अपना ज्ञानवर्धन करने और क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं।

अप्रैल का महीना इस संगठन के लिए बहुत ही दुखदायी था। महीने के शुरुआत में, हमने अपने दो प्रिय अधिकारी, श्री जितेंद्र पँवार, निदेशक और श्री एल. कोदंदरामास्वामी, उप-निदेशक को उनकी ड्यूटी के दौरान खो दिया। कर्नाटक की एक परियोजना के जांच दौरे से लौटते समय वे भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गए। हम अपने अधिकारियों के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और अपूर्णीय क्षति के लिए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। महीने के दौरान कोविड-19 के मामलों में भी अभूतपूर्व उछाल देखा गया। एक संगठन के रूप में केंद्रीय जल आयोग भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ और इसने अपने कई अधिकारी/कर्मचारी इस महामारी में खो दिए। ये संगठन, साथ ही साथ देश के लिए एक दुखदायी अनुभव तथा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। मैं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूँ और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

मैं प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करता हूँ कि वे समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करें और कोविड-19 का ध्यान रखते हुए उचित व्यवहार करें। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके परिवारों को टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। टीकाकरण को 18 वर्ष की आयु तक के लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है।

गौतम शर्मा

विषय सूची

- देश में ग्लेशियर प्रबंधन
- एनएचपी के अंतर्गत एनआरएससी द्वारा ज्ञान उत्पादों का विकास
- उत्तरी कोयल परियोजना की तकनीकी मूल्यांकन समिति की 30वीं बैठक
- सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता
- सरस्वती नदी का संरक्षण तथा इसकी विरासत की विकास परियोजना

- शाहपुर कांडी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) की समीक्षा
- द्वितीय रावी-व्यास संधि के लिए डीपीआर की तैयारी
- भारत-यूरोप जल साझेदारी
- हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का प्रयोग करके जलाशय अवसादन का अध्ययन
- भारत के जलक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर वेबिनार श्रृंखला
- रायपुर प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल मान्यता

- सातवाँ भारत जल-सप्ताह – प्रारम्भिक गतिविधियाँ
- वित्तीय प्रगति
- जल क्षेत्र समाचार
- भारत में जल संसाधनों के आंकलन का इतिहास- डेटा कॉर्नर
- जलाशय निगरानी
- गैलरी
- पोलावरम परियोजना – प्रगति
- शोक-संदेश
- इतिहास- सर आर्थर कॉटन

देश में ग्लेशियर प्रबंधन- ग्लेशियर झीलों के फटने से हिमालय क्षेत्र में अचानक बाढ़ सहित ग्लेशियरों/ग्लेशियर-झीलों की निगरानी

जल संसाधनों पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक 08.04.2021 को बुलाई गई। यह बैठक उपरोक्त विषय- "देश में ग्लेशियर प्रबंधन- ग्लेशियर झीलों के फटने से हिमालय क्षेत्र में अचानक बाढ़ सहित ग्लेशियरों/ग्लेशियर-झीलों की निगरानी" के परीक्षण से संबन्धित थी। इस बैठक के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसेकि जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

एनएचपी के अंतर्गत एनआरएससी द्वारा ज्ञान उत्पादों के विकास के संबंध में बैठक

ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. के सचिव ने 20.04.2021 को एनएचपी के अंतर्गत एनआरएससी द्वारा ज्ञान उत्पादों के विकास के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान एनआरएससी द्वारा दो उत्पादों पर प्रस्तुति दी गई थी जिनका नाम था; भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्र में ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ के खतरे का मूल्यांकन और स्थानिक बाढ़ पूर्व प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली- गोदावरी व तापी।

भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्र में ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ के खतरे का मूल्यांकन

प्रस्तुति के दौरान, एनआरएससी ने सूचित किया कि उन्होंने सिंधु बेसिन के 0.5 हेक्टेयर से अधिक आकार की ग्लेशियर झीलों की सूचना तैयार की है और उसका विमोचन ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. के सचिव द्वारा किया गया। यह भी बताया गया कि गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए सूची तैयार करने का कार्य अभी प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन के अन्य उद्देश्य हैं:

- महत्वपूर्ण ग्लेशियर झीलों का श्रेणीकरण तथा चयन
- प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण झीलों के लिए ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ के खतरे का मूल्यांकन; और
- ग्लेशियर झील के फटने से होने वाले बाढ़ के खतरे को समझने के लिए दृश्य प्रणाली

उत्तर कोयल परियोजना की 30वीं तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) की बैठक

उत्तर कोयल परियोजना का शेष कार्य पूरा करने के लिए श्री कुश्विंदर वोहरा, सदस्य(डब्ल्यू पी&पी), केंद्रीय जल आयोग तथा अध्यक्ष, टीईसी, एनकेपी की अध्यक्षता में तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) की 30वीं बैठक 12.04.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से के.ज.आ., मुख्यालय में आयोजित की गई। ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., केंद्रीय जल आयोग मुख्यालय और क्षेत्र इकाइयाँ, सीएसएमआरएस, बिहार और झारखंड की राज्य सरकार तथा वैपकोस के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

उत्तर कोयल परियोजना उत्तर कोयल नदी पर स्थित है जो सोन नदी की सहायक नदी है। यह परियोजना पूरा होने पर बिहार और झारखंड को लाभ प्रदान करेगी। बैठक के दौरान, परियोजना की प्रगति की गहन समीक्षा की गई और विभिन्न कार्य बिंदुओं की पहचान की गई।

बिहार सरकार के प्रतिनिधियों से बिहार राज्यकेहिस्से में राइट मैन कैनाल (आरएमसी) के लिए कैबिनेट की मंजूरी और आगे की निविदा गतिविधियों की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बिहार में राइट मैन कैनाल

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। संबन्धित मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिया गया कि वे एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें जो दो पृष्ठ से अधिक का न हो और उस नोट में बैठक के दौरान जिन विविध समस्याओं पर चर्चा की गई थी उनके समाधान की व्याख्या करें। मांगा गया आवश्यक संक्षिप्त नोट सभी मंत्रालयों/विभागों ने प्रस्तुत किया।

उत्पादों के विकास के संबंध में बैठक

स्थानिक बाढ़ पूर्व प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली- गोदावरी व तापी

इस अध्ययन के उद्देश्य हैं:

- अंतरिक्ष आधारित आदानों का उपयोग करके गोदावरी और तापी नदियों के लिए मध्यम अवधि की बाढ़ पूर्व चेतावनी मॉडल विकसित करना
- उच्च विभेदन डिजिटल उन्नयन मॉडल का उपयोग करके स्थानिक बाढ़ आप्लावन सिमुलेशन मॉडल विकसित करना
- एक वेब-सक्षम रीयल-टाइम स्थानिक बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए
- बाढ़ घटना के दौरान संबंधित अधिकारियों को बाढ़ परामर्श जारी करने के लिए कार्यप्रवाह तंत्र विकसित करना
- विभिन्न रिटर्न पीरियड की बाढ़ के तहत दोनों घाटियों में बाढ़ संभावित क्षेत्र का वैज्ञानिक मूल्यांकन

अब तक, एनआरएससी ने बाढ़ की आशंका वाले क्रिटिकल पहुंच वाले 0.5 मीटर के उच्च रिज़ॉल्यूशन डीईएम प्राप्त कर लिया है और बाकी क्षेत्रों के लिए कार्टो डीईएम का अधिग्रहण कर लिया गया है। ऐतिहासिक डेटा के आधार पर दोनों बेसिनों के लिए मॉडल विकसित, कैलिब्रेटेड और मान्य किया गया है। इस मानसून के दौरान इसका वास्तविक समय पर परीक्षण किया जाएगा।



(आरएमसी)हिस्सेकी पूरी लाइनिंग के मुद्दे के बारे में जल्द से जल्द अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा मदों जैसे भूमि अधिग्रहण की स्थिति, मैसर्स वैपकोस द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, आरएमसी में नहर के अस्तर में एलडीपीई शीट की मोटाई का मुद्दा, वितरण प्रणाली की डिजाइन और ड्राइंग, केंद्रीय सहायता जारी करने के प्रस्तावों की सिफारिश आदि पर चर्चा हुई।



सीएनएस प्रोफाइल राइट मैन केनाल (आरएमसी) - उत्तरी कोयल परियोजना के लिए कार्य प्रगति पर है



आरएमसी में 18.9 किमी पर एसएलआर ब्रिज के एबटमेंट शाफ्ट (आरएचएस) के लिए पहली लिफ्ट कास्टिंग

सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता (एसआईएमपी) की समीक्षा तथा राज्यों के साथ परामर्श बैठकें

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यू पी&पी), के.ज.आ. ने सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता की समीक्षा के लिए 15.04.2021 को वीसी के माध्यम से एक बैठक बुलाई। बैठक में श्री पी. दोर्जे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता (पोमियो), सीडब्ल्यूसी और पोमियो, सीडब्ल्यूसी के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान, की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को दृढ़ करने के साथ-साथ इसके लिए समय-सीमा भी तय की गई। सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने भी इस संबंध में शीघ्र ही एडीबी अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाने की इच्छा व्यक्त की।

पिछले वर्ष, केन्द्रीय जल आयोग, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की तकनीकी सहायता से "सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता" (एसआईएमपी) शुरू किया है। सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता, सिंचाई जल उपयोग दक्षता तथा फसल जल उत्पादकता को सुधारने हेतु, भारत में वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का प्रस्ताव रखता है। इसे 4 चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। एसआईएमपी चरण -1 जारी है और जून, 2021 तक जारी रहेगा। पोमियो, सीडब्ल्यूसी कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सलाहकारों के समर्थन से केंद्रीय सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यालय (सीआईएमओ) के रूप में कार्य कर रहा है। एसआईएमपी के तहत परियोजनाओं के पहले बैच के रूप में, देश से 3-4 एमएमआई परियोजनाएं जो कम पानी के उपयोग की दक्षता या कम परियोजना प्रदर्शन के मुद्दे से जूझ रही हैं, उन्हें सिंचाई आधुनिकीकरण योजना (आईएमपी) तैयार करने के लिए पहचाने जाने की परिकल्पना की गई है। चरण 4 में सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना का अंतिम कार्यान्वयन होगा। इसका उद्देश्य यह है कि उपरोक्त प्रक्रिया को तब तक लगातार दोहराया जाएगा जब तक कि देश में अधिकांश सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण नहीं हो जाता।

चरण 1 गतिविधियों के तहत, सचिव (ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि.) की उपस्थिति में 08.12.2020 को एक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसके दौरान सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को एसआईएमपी से परिचित कराया गया था और कार्यक्रम, इसके दायरे, वर्कफ्लो, कार्यान्वयन व्यवस्था आदि के बारे में बातचीत की गई थी। साथ ही राज्यों से एसआईएमपी के तहत बैच-1 के रूप में



एसआईएमपी समीक्षा बैठक

विचारार्थ प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

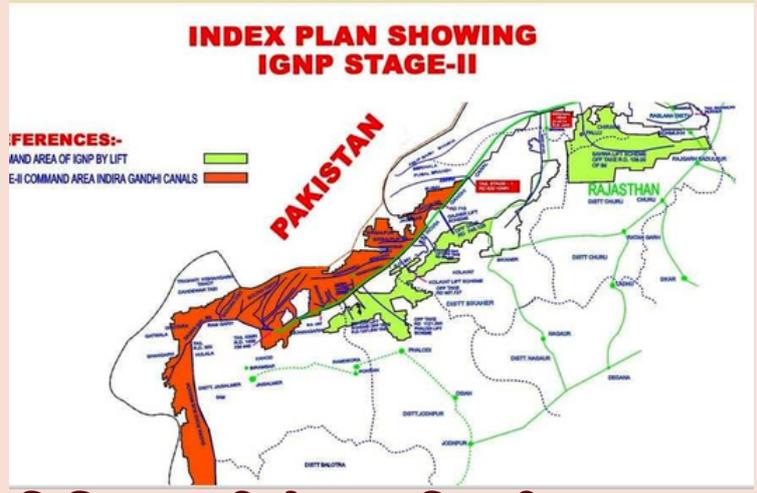
परामर्श बैठक

चरण -1 बैच -1 के तहत, केवल 3 से 4 योजनाओं को आधुनिकीकरण योजना और डीपीआर तैयार करने के लिए लिया जाना है, अतः एसआईएमपी टीम ने प्रारंभिक 12 परियोजनाओं के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श शुरू किया।

अप्रैल -2021 में महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक राज्य के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें निम्नलिखित परियोजनाओं पर चर्चा की गई।

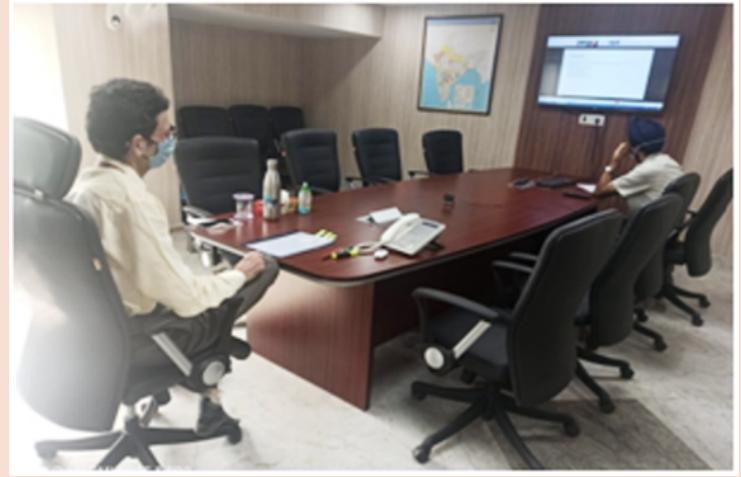
परामर्श की तिथि	राज्य	परियोजनाओं पर चर्चा	द्वारा प्रस्तुत विवरण
28.04.2021	महाराष्ट्र	पालखेड परियोजना	श्री संजय बेलसारे, मुख्य अभियंता, नासिक
		पूर्णा परियोजना	श्री सब्बिनवार, अधीक्षण अभियंता, नांदेड सिंचाई मण्डल, नांदेड
29.04.2021	राजस्थान	इंदिरा गांधी परियोजना (आईजीएनपी) चरण-II	श्री विनोद कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता (आईजीएनपी), बीकानेर
		चंबल परियोजना	श्री आशिम मार्कंडेय, मुख्य अभियंता, जयपुर
30.04.2021	कर्नाटक	वनिविलासासागर परियोजना	श्री राघवन, मुख्य अभियंता, यूबीपी जोन, चित्रदुर्ग

प्रस्तुति के बाद, सीडब्ल्यूसी और सलाहकारों की टीम द्वारा कई स्पष्टीकरण मांगे गए। राज्यों से आवश्यक अतिरिक्त जानकारी को सूचीबद्ध करने और प्रसारित करने का निर्णय लिया गया।



सरस्वती नदी का संरक्षण तथा इसकी विरासत की विकास परियोजना की समीक्षा

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी ने सरस्वती नदी संरक्षण और इसकी विरासत विकास परियोजना की मंजूरी/ डिजाइन परामर्श की स्थितिकी समीक्षा के लिए 15.04.2021 को वीसी के माध्यम से एक बैठक बुलाई।



बैठक में सीडब्ल्यूसी के विभिन्न विंगों के साथ-साथ यूवाईआरबी के अधिकारियों ने भाग लिया। विभिन्न मंजूरीयों की स्थिति, राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना/डेटा और मूल्यांकन/डिजाइन परामर्श आदि की समाप्ति की समय-सीमा पर चर्चा की गई। सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी ने काम पूरा करने के लिए एक समयरेखा तैयार करने पर जोर दिया। परियोजना अधिकारियों के साथ शीघ्र ही समग्र प्रगति की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया।

शाहपुरकंडी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की छठी बैठक

शाहपुरकंडी बांध परियोजना (एसकेडीपी) के कार्यान्वयन के लिए निगरानी समिति की छठी बैठक 19.04.2021 को श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें मुख्य बांध, हाइडल चैनल हेड रेगुलेटर, रावी नहर हेड रेगुलेटर, हाइडल चैनल, मुख्य बांध और हाइडल चैनल हेड रेगुलेटर पर हाइड्रो मैकेनिकल कार्य, पावर हाउस आदि मुद्दों पर भौतिक कार्य की प्रगति के संबंध में चर्चा की गई। उपरोक्त के अलावा, लिंक चैनल (जम्मू और कश्मीर), भूमि अधिग्रहण, वित्तीय प्रगति, पुल सहित लखनपुर बसोहली रोड के पुनर्संरक्षण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अन्य वैधानिक मंजूरी की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई और इससे संबंधित कार्यों को परियोजना अधिकारियों को प्रदान किया गया।



परियोजना प्राधिकरण ने 24.11.2020 को आयोजित 12वीं हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी (एचपीएससी) की बैठक के दौरान पंजाब और जम्मू-कश्मीर की तरफ रेगुलेटर के शिखर स्तर को कम करने का मुद्दा उठाया। इस मामले की जांच 5वीं निगरानी बैठक और बाद की बैठकों के दौरान की गई थी जो क्रमशः 29.01.2021 और 08.02.2021 को आयोजित की गई थीं। 19.04.2021 को आयोजित छठी निगरानी बैठक के दौरान, परियोजना प्राधिकरण, पंजाब ने बताया कि उनकी आंतरिक डिजाइन स्तर की बैठक 15.04.2021 को हेड रेगुलेटर के

स्तर के मुद्दे को हल करने के लिए आयोजित की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 08.09.2018 के समझौते के अनुसार क्रेस्ट स्तर 398.4मी पर रखा जाएगा और तदनुसार, जम्मू-कश्मीर सरकार को भी यह बताने के लिए पंजाब सरकार से सिफारिश की।

(बी) विषयगत क्षेत्र/स्तंभ-सिंचाई जल उपयोग दक्षता

यूरोपीय संघ/जीआईजेड के प्रतिनिधियों और सिंचाई जल उपयोग दक्षता विषयगत स्तंभ के नोडल अधिकारियों के बीच 15.04.2021 को तीन पायलट परियोजनाओं नामतः: महुआर, लोअरपंजारा और गोलावागु के लिए जल उपयोग दक्षता के आकलन हेतु डेटा आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में लिए गए व्यापक निर्णय निम्नानुसार हैं:

- सिंचाई जल उपयोग दक्षता पर कार्य क्षेत्र की लचीली आईईडब्ल्यूपी कार्य योजना तैयार करने और लागू करने के लिए एक तकनीकी कार्य समिति का गठन किया जाएगा। समिति में जल शक्ति मंत्रालय (सीडब्ल्यूसी प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों सहित), संबंधित राज्य जल संसाधन / सिंचाई विभाग और आईईडब्ल्यूपीजीआईजेड परियोजना प्रबंधन इकाई के अधिकारी शामिल होंगे।
- IEWP परियोजना प्रबंधन इकाई बैठक के प्रतिभागियों को पहले IEWP चरण की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।

(सी) विषयगत क्षेत्र/स्तंभ-नदी बेसिन प्रबंधन

आईईडब्ल्यूपी के कार्य चरण -2 के नदी बेसिन प्रबंधन कार्य क्षेत्र के लिए फ्लेक्सिबल आईईडब्ल्यूपी कार्य योजना की रूपरेखा बनाने और चर्चा करने के लिए 13.04.2021 को ईयू/जीआईजेड प्रतिनिधियों और नदी बेसिन प्रबंधन विषयगत स्तंभ के नोडल अधिकारियों के बीच एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में लिए गए व्यापक निर्णय इस प्रकार हैं:

- एनएमसीजी के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि वे आरबीएम योजना विकसित करने के लिए तापी आरबीएम योजना के दृष्टिकोण और विशेषज्ञता से गंगा बेसिन में एक उप-बेसिन को दोहराने के इच्छुक हैं। एनएमसीजी ने ऐसे संभावित ज्ञान हस्तांतरण के लिए रामगंगा उप-बेसिन, पूर्वी काली उप-बेसिन और गोमती उप-बेसिन की पहचान की है।
- आईईडब्ल्यूपी चरण -2 के सभी कार्य क्षेत्रों के दायरे की सामान्य समझ रखने के लिए राष्ट्रीय जल अकादमी, सीडब्ल्यूसी, पुणे, शुरू से ही सभी कार्य क्षेत्रों में शामिल होगी। यह क्षमता निर्माण योजना को दायरे के अनुरूप विकसित करने और ज्ञान प्रसार के लिए मॉड्यूल विकसित करने में मदद करेगा।
- आईईडब्ल्यूपी / जीआईजेड मसौदा कार्य योजना को बीपीएमओ, सीडब्ल्यूसी के साथ साझा करेगा और मुख्य अभियंता, बीपीएमओ के कार्यालय के माध्यम से, इसे प्रतिक्रिया के लिए सभी आरबीएम नोडल अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा।

तीन पायलट कमांडों में सिंचाई प्रदर्शन मूल्यांकन पर पहले चरण IWEP में विकसित रिपोर्ट परिचालित की जाएगी। इसके साथ ही, डेटा अंतराल के कारण चरण -1 में आने वाली चुनौतियों पर एक नोट प्रदान किया जाएगा।

- समिति यूरोपीय संघ के विशेषज्ञ के साथ सिंचाई दक्षता और प्रदर्शन मूल्यांकन अध्ययन के लिए डेटा आवश्यकताओं पर चर्चा करेगी।
- चयनित पायलट परियोजनाएं बहुत नई थीं और जलाशय रिलीज के साथ-साथ नहर प्रणाली निगरानी, फसल उगाने के तरीके आदि पर और दीर्घकालिक समय-अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इस डेटा अंतराल को दूर करने के लिए, डेटा की आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर नई (अलग) परियोजनाओं/पायलटों का चयन किया जा सकता है। एससीएडीए आधारित निगरानी प्रणाली वाली परियोजनाओं को उनकी डेटा उपलब्धता और इस विषयगत क्षेत्र हेतु उपयुक्तता के लिए खोजा जाएगा।



- आईईडब्ल्यूपी संयोजक के साथ समन्वय में, जीआईजेड द्विपक्षीय बैठकों के लिए सभी नोडल अधिकारियों से संपर्क करेगा ताकि फीडबैक पर चर्चा की जा सके और आरबीएम के लिए आईईडब्ल्यूपी कार्य योजना के मसौदे को अद्यतन किया जा सके। इसके बाद एक संयुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक में कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी तथा सहमति ली जाएगी जिसमें सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी के कार्यालय के साथ-साथ यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल को शामिल होंगे।
- आईईडब्ल्यूपी कार्य योजना के कार्यान्वयन में समन्वित प्रयासों के लिए तापी नदी बेसिन समिति को आईईडब्ल्यूपी की कार्य योजना प्रदान की जाएगी

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	दिनांक एवं अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	श्रेणी
a)	बाढ़ पूर्वानुमान और माइक मॉडलिंग	19-30 अप्रैल 2021 (2 सप्ताह)	97	तकनीकी(पीओडीएल)
b)	जीआईएस का उपयोग कर जल निकासी और वाटरशेड चित्रण	19-30 अप्रैल 2021 (2 सप्ताह)	37	तकनीकी(पीओडीएल)
c)	मीडिया पेशेवरों के लिए जल संसाधन क्षेत्र के अवलोकन पर प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला	26-30 अप्रैल 2021	25	जन जागरूकता

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजनाओं (एनएचपी) चरण -1 के तहत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए जलाशय अवसादन अध्ययन

जलाशय अवसादन एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है और जल क्षेत्र में अत्यधिक महत्व के विषयों में से एक है। सीडब्ल्यूसी ने राष्ट्रीय महत्व के लगभग 191 जलाशयों का अवसादन सर्वेक्षण करने की योजना बनाई है। इस अध्ययनके लिए, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) हेतु 30 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। अध्ययन का चरण -1 फरवरी, 2021 के महीने में शुरू किया जा चुका है, जिसमें राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार राज्यों के 32 जलाशयों को लिया

गया है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) चरण -1 के तहत भारत में 32 जलाशयों के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग करके जलाशय अवसादन अध्ययन की मासिक प्रगति समीक्षा के लिए सीडब्ल्यूसी, मुख्यालय में मुख्य इंजीनियरिंग (ईएमओ), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में 13.04.2021 को बैठक आयोजित की गई थी। समिति के सदस्यों द्वारा टीवीआईपीएल प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत मार्च 2021 की मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

एनएचपी- अवसादन सर्वेक्षण के लिए जलाशयों की सूची- चरण 1

क्र.सं.	राज्य	बांध का नाम	नदी का नाम	नदी सकल संग्रहण (एमसीएम)	जलाशय क्षेत्र (वर्गकिमी)	लाइवभंडारण (एमसीएम)
1	बिहार	ओरहनी	ओरहनी	51.56	9.95	44.59
2	बिहार	अंजन	अंजन	26.68	3.44	24.71
3	बिहार	बिलाशी	बिलाशी	32.57	5.83	28.87
4	हिमाचल प्रदेश	कोल	सतलुज	576	13	90
5	कर्नाटक	लिंगनमक्की	शरवती	4435.35	320	4,294.00
6	कर्नाटक	सुपा	कालिंदी	4178	123	3,758.00
7	कर्नाटक	मणि	वाराही	961.75	56	883.81
8	कर्नाटक	कदरा बांध	काली	388.92	37.75	209.06
9	कर्नाटक	थातिहल्ला	काली नाड़ी	264.03	27.3	249.26
10	कर्नाटक	गेरुसोप्पा बांध	शरवती	130.89	6	58.21
11	कर्नाटक	तालाकले बांध	शरवती	129.61	9.32	14
12	कर्नाटक	सवेहाकालू बांध	सवेहक्लू	124.97	9.4	66.97
13	राजस्थान	राणाप्रतापसागर	चंबल	2899	198	1,567.00
14	राजस्थान	बीसलपुर	बनास	1095.84	213	938.69
15	राजस्थान	जवाई	जवाई	198.2	25.8	184.2
16	राजस्थान	सोम कमला अंबा सोम और गोमती	गोमती	172.8	36.18	106.3
17	राजस्थान	जाखम	जाखम	142.02	11.9	132.28
18	राजस्थान	पार्वती बांध	चंबल	120.28	24.08	108.6
19	राजस्थान	कोटा बैराज	चंबल	112.06	5.82	69.83
20	राजस्थान	राजसमंद	गोमती बनास	107.2	16.5	98.71
21	तमिलनाडु	मेडूर	कावेरी	2707.128	138.75	2,647.00
22	तमिलनाडु	परम्बिकुलम	परम्बिकुलम	504.66	20.72	380
23	तमिलनाडु	वैगई	वैगई	172.4	24.2	169.55
24	तमिलनाडु	अलियार	अलियार	109.43	6.48	106.12
25	तमिलनाडु	भवानी सागर	भवानी	813.44	72.7	792
26	तमिलनाडु	मणिमुथर	मणिमुथर	156.07	9.4	156.07
27	तमिलनाडु	शोलायर (मुख्य)	चलक्कुडी	153.48	8.705	150.08
28	तमिलनाडु	पेछिपराई	कोडियार	150.16	15.15	123.19
29	तमिलनाडु	अमरावती	अमरावती	114.53	9.06	109.36
30	तमिलनाडु	सथानुर	पेन्नैयार	207.18	18.1	19.852
31	तमिलनाडु	पूंडी	कोसस्थलियार	91.437	33.63	91.147
32	तमिलनाडु	तिरुमूर्ति	भरतपुझा	54.79	3.88	49.39
		कुल		21483.605	1518.565	17827.419

आगामी कार्यक्रम- भारत में जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर वेबिनार श्रृंखला (07-जून -23 अगस्त, 2021)

अधिकांश अन्य संसाधनों के विपरीत जल राजनीतिक सीमाओं का पालन नहीं करता है। जल का प्राकृतिक प्रवाह, पृथ्वी की सतह और भूमिगत दोनों पर नियमित रूप से प्रशासनिक सीमाओं को पार करता है। यही कारण है कि दुनिया के मीठे पानी के संसाधनों को कई देशों द्वारा साझा किया जाता है। 263 ट्रांसबाउंड्री झील और नदी घाटियाँ हैं जो पृथ्वी की सतह के लगभग आधे हिस्से को कवर करती हैं। इन बेसिनों में 145 देशों की सीमाएँ आती हैं और 30 देश पूरी तरह से इनके भीतर स्थित हैं। लगभग 300 ट्रांसबाउंडरी एक्वीफर हैं, जो भूजल पर निर्भर 2 बिलियन लोगों की सेवा करने में मदद करते हैं। झीलों, नदियों और जलभृतों का अत्यधिक दोहन नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल सकता है और जल आपूर्ति की विश्वसनीयता और स्थिरता के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव और संघर्ष का कारण बन सकते हैं।

भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। विश्व की कुछ प्रमुख नदी प्रणालियाँ (जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र) इस उपमहाद्वीप में हैं और ये सभी नदी प्रणालियाँ सीमा पार हैं। सिंधु और गंगा के हिस्से और ब्रह्मपुत्र के हिस्से के मामले में, भारत अपर राईपेरियन है और यह गंगा के हिस्से और ब्रह्मपुत्र के हिस्से में लोवर राईपेरियन है। इसलिए भारतीय संदर्भ में भी इन नदी घाटियों के विकास और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में, भारत ने जल विकास और प्रबंधन में साझा ज्ञान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सर्वोत्तम प्रथाओं से पारस्परिक रूप से लाभ उठाने के लिए विभिन्न देशों के साथ सहयोग भी स्थापित किया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय जल अकादमी, सीडब्ल्यूसी, पुणे 07.06.2021 से 23.08.2021 तक "भारत में जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" पर वेबिनार श्रृंखला आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोई पाठ्यक्रम शुल्क नहीं है। सभी वार्ताएं/व्याख्यान एनडब्ल्यूए सिस्को वेबएक्स मीटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे। वेबिनार में भाग लेने के लिए लिंक ईमेल के माध्यम से सभी अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा और वेबिनार शुरू होने से पहले एनडब्ल्यूए की वेबसाइट (<https://nwa.mah.nic.in>) पर आगामी ईवेंट के लिए भी लिंक पेज दिए जाएंगे। तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए वाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा।

जल और बाढ़ प्रबंधन प्रणाली पर समय पर निर्णय लेने और अग्रिम सूचना देने के लिए पूर्वानुमान विश्लेषण पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुति

जल और बाढ़ प्रबंधन प्रणाली पर समय पर निर्णय लेने और अग्रिम सूचना देने के लिए पूर्वानुमान विश्लेषण पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15.04.2021 को प्रस्तुति आयोजित की गई। एसएसएस

रायपुर प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल मान्यता अप्रैल-2021 के महीने में आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार रायपुर प्रयोगशाला, एमईआरओ, सीडब्ल्यूसी के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त हुई है। अब, सीडब्ल्यूसी के पास पूरे भारत में कुल 23 प्रयोगशालाओं में से 15 एनएबीएल मान्यता प्राप्त जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं हैं।



National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
(A Constituent Board of Quality Council of India)

NABL / T-5918 06.04.2021

NIRMAL KUMAR BHUVAN
MAHANADI BASIN RIVERS WATER QUALITY LABORATORY
KENDRIYA JAL AYOOG, FIRST FLOOR, KOTA
COLONY, PO-R S UNIVERSITY
RAIPUR, CHHATTISGARH-492010
Mobile: 9937344601
E-mail: rkbhuvan-cwc@nic.in

Subject: Grant of accreditation

Dear Sir,

NABL is pleased to inform you the grant of accreditation in accordance with ISO/IEC 17025:2017 in the discipline of Chemical testing as per the scope recommended by the assessment team.

All the personnel proposed by the laboratory to report, review and authorize the results are accepted.

Your laboratory's accreditation is valid w.e.f. 05.04.2021 to 04.04.2023. The accreditation certificate number is TC- 9397 which is currently in the process of preparation.

The accreditation is subjected to surveillance within a year as per NABL norms during the accreditation period. You are advised to adhere NABL 131 and use NABL symbol in line with NABL 133.

NABL is now allowing its accredited CABs (testing, calibration and medical laboratories) to use NABL Accredited CAB Combined ILAC MRA Ma on their test / calibration reports through a valid Agreement. For more details, please refer NABL document NABL 133 available on NABL website www.nabl-india.org under publication section.

Yours Sincerely,
Vivek Varthan
vivek@nabl.org

NABL House, Plot 45, Sector 44, Gurugram 122 003, Haryana, India
Tel. No.: +91-124-4679700 (30 lines) * Fax: +91-124-4679799 * Website: www.nabl-india.org





International Cooperation in Water Sector of India



Weekly Webinar Series

07 June – 23 August 2021

Every Monday
11:00 AM – 12:30 PM

No Participant Fee



Last Date to Register
03 June 2021

Scan to Register

सातवें भारत जल सप्ताह -2021 की वैज्ञानिक समिति के कोर ग्रुप की पांचवी बैठक

सातवें भारत जल सप्ताह-2021 की वैज्ञानिक समिति के कोर ग्रुप की पांचवी बैठक 01.04.2021 को कें.ज.आ. के मुख्यालय में आयोजित की गई। इसमें अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य, के.ज.आ. तथा के.ज.आ., एनडब्ल्यूडीए, आईसीआईडी के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रारंभ में, श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, एनडब्ल्यूडीए ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और आयोजन समिति के सदस्यों के विचारों / सुझावों से अवगत कराया जिसकी अध्यक्षता सचिव,

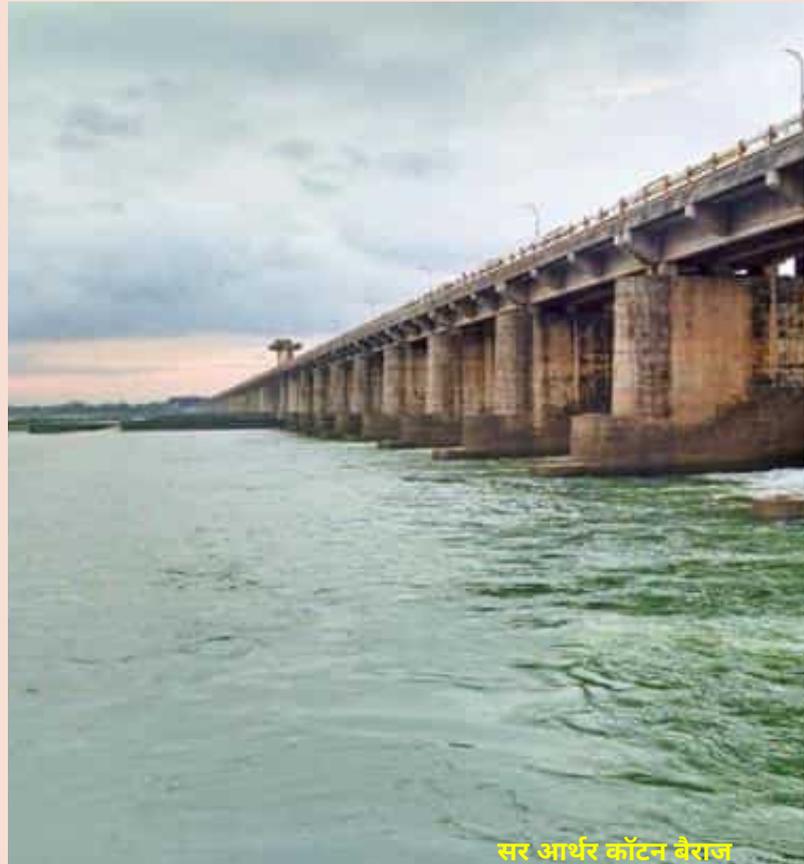
ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि.ने की थी। सेमिनारों और पैनल चर्चाओं के लिए विषयों/विषयों की विशिष्टता में सुधार के लिए चर्चाएँ की गई।

आयोजन समिति ने उन्हें और अधिक व्यापक बनाने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय विकास के साथ संरेखित करने का भी सुझाव दिया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, कोर ग्रुप ने नीचे दी गई तालिका में वर्णित विषयों को अंतिम रूप दिया:

क्रमांक	संगोष्ठी	पैनल चर्चा
1	सतत कृषि और जल प्रबंधन - आर्थिक विकास की कुंजी	सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जल की भूमिका
2	भूजल संसाधनों की सततता के लिए चुनौतियाँ	जल सुरक्षासुनिश्चित करते हुए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना - चुनौतियाँ और अवसर
3	जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और अनुकूलन रणनीतियाँ	मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ
4	जल संबंधी आपदाओं का प्रबंधन - बाढ़ और सूखा	ऊर्जा सुरक्षा के लिए जलविद्युत की भूमिका
5	कुशल जल प्रबंधन के लिए उभरते तकनीकी समाधान	राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की ओर अभिसरण - आईबीडब्ल्यूटी
6	पर्यावरण और आजीविका के लिए जल	जल प्रबंधन के लिए विकेन्द्रीकृत समाधान
7	जल क्षेत्र में गुणवत्ता चुनौतियाँ	जल शिक्षा, जन जागरूकता और मीडिया की भूमिका
8	एक सहयोगात्मक जल अभिशासन व्यवस्था की स्थापना	महामारी के दौरान कृषि स्थिरता
9	जल प्रबंधन के लिए सूक्ष्म और बड़े हस्तक्षेप का मेल करना	कुशल जल प्रबंधन में सिविल सोसाइटी की भूमिका
10	वाटर रेजिलिएन्स और जल बाजार के लिए अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण	शहरी जल योजना और प्रबंधन में चुनौतियाँ

जल विज्ञान अध्ययन

- जल विज्ञान अध्ययन संगठन (एचएसओ), सीडब्ल्यूसी ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अयोध्या में सरयू नदी (घाघरा) पर प्रस्तावित अयोध्या बैराज के जल विज्ञान अध्ययन के लिए एक परामर्श कार्य लिया था। घाघरा एक बारहमासी नदी है जो मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से निकलती है। नदी नेपाल से होकर गुजरती है और भारत में ब्रह्मघाट पर शारदा नदी में मिल जाती है। नदी को नेपाल में करनाली के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के रेवेलगंज में गंगा नदी में मिलने से पहले नदी लगभग 1080 किमी की दूरी तय करती है। जल उपलब्धता की गणना, डिजाइन बाढ़ और टेल वाटर रेटिंग कर्व अध्ययन सहित हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन पूरा कर लिया गया है और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।
- सर आर्थर कॉटन बैराज का डिजाइन बाढ़ अध्ययन एचएसओ, सीडब्ल्यूसी द्वारा पूरा कर लिया गया है। सर आर्थर कॉटन बैराज (SACB) एक सिंचाई संरचना है जिसे मूल रूप से आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी के निचले हिस्से पर राजमुंदरी में 1850 में बनाया गया था। गोदावरी नदी बैराज से लगभग 50 मील दूर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।



सर आर्थर कॉटन बैराज

30.04.2021 की स्थिति के अनुसार योजनाओं/घटकों की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान (2021-22)	व्यय (अप्रैल, 2021)	व्यय (%में)
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली(डीडब्ल्यूआरआईएस) का विकास	166.100	1.494	0.9
2.	जल संसाधन विकास योजनाओं (आईडब्ल्यूआरडी) की जांच	12.00	0.764	6.37
3.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमवीएपी)	27.408	0.800	2.92
4.	अवसंरचना विकास (आईडी) योजनाएं	4.500	0.00	0.00
5.	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी)	25.000	0.08	0.32

जल क्षेत्र समाचार

- 4 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन : कटारिया (राष्ट्रीय सहारा, 03.04.2021)
- 4 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन : कटारिया (राष्ट्रीय सहारा, 03.04.2021)
- घर—घर निर्बाध स्वच्छ पानी की सप्लाई के लिए हरियाणा व यूपी से मिलने वाले सिंचाई जल का होगा इस्तेमाल (दैनिक भास्कर, 06.04.2021)
- भाखड़ा डैम में रोज एक फीट घट रहा पानी, गर्मी के साथ जल संकट गहराया (दैनिक भास्कर, 06.04.2021)
- कोरोना से बचाव के साथ ही जल संरक्षण पर भी ध्यान दें, छोटी नदियों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करें (हरिभूमि, 06.04.2021)
- सिंचाई वाले पानी से दिल्ली वालों की प्यास बुझाने की तैयारी में सरकार (हरिभूमि, 06.04.2021)
- नमामि गंगे से जुड़ी परियोजनाओं को 15 जून तक पूरा करें : महेन्द्र सिंह (द पायनियर, 07.04.2021)
- यमुना प्रदूषित करने पर डीपीसीसी ने लगाया 12 करोड़ रुपए का जुर्माना (दैनिक जागरण, 08.04.2021)
- लद्दाख : पहाड़ी गांवों में भी नल से जल का सपना होगा साकार (राष्ट्रीय सहारा, 10.04.2021)
- केनबेतवा परियोजना से पन्ना बाघ अभयारण्य को क्षति : सोनिया (राष्ट्रीय सहारा, 10.04.2021)
- साफ पानी के लिए जूझ रहे 2.2 अरब लोग (नवभारत टाइम्स, 11.04.2021)
- जम्मू—कश्मीर को अगले साल से मिलेगा रावी का पाकिस्तान जाने वाला पानी (अमर उजाला, 11.04.2021)
- तिब्बत में 'सुपर डैम' बनाएगा चीन, ब्रह्मपुत्र का पानी भारत में जाने से रोक सकता है (नवभारत टाइम्स, 12.04.2021)
- तिगुनी बिजली उत्पादन करने के लिए तिब्बत में बड़े डैम (हरिभूमि, 12.04.2021)
- स्वच्छ गंगा निधि कोष में छह वर्षों में 453 करोड़ मिले (राष्ट्रीय सहारा, 16.04.2021)
- राजधानी में पानी की कमी के लिए हरियाणा और पंजाब जिम्मेदार (अमर उजाला, 16.04.2021)
- सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांचेगी पानी की गुणवत्ता—मात्रा (दैनिक जागरण, 20.04.2021)
- विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली (राजस्थान पत्रिका, 22.04.2021)
- महाराष्ट्र को हर घर नल के लिए 3000 करोड़ (राष्ट्रीय सहारा, 23.04.2021)
- चमोली में भारत—चीन सीमा के पास ग्लेशियर टूटा, रेणी में ऋषिगंगा का जलस्तर बढ़ा (पंजाब केसरी, 24.04.2021)

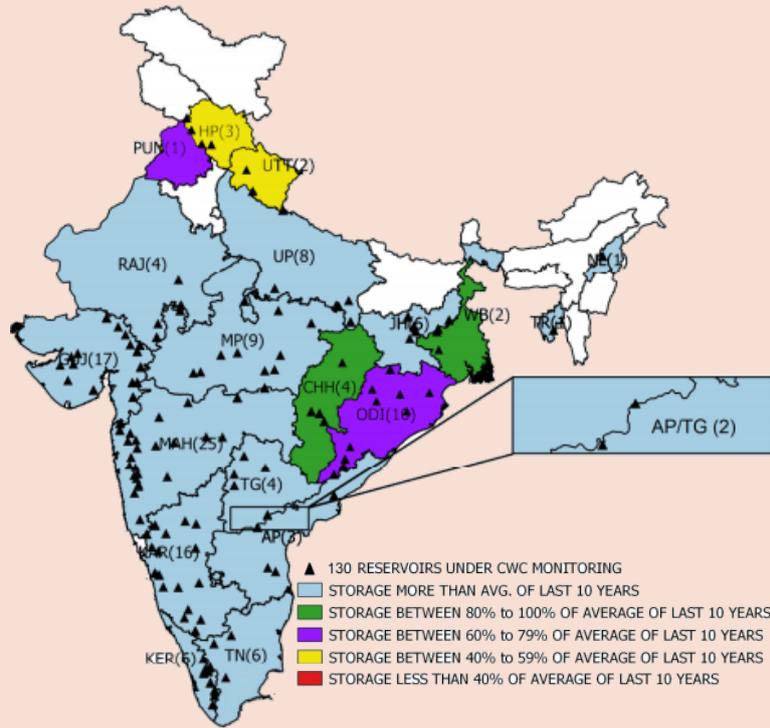
डेटा कॉर्नर-भारत में जल संसाधन आंकलन का इतिहास

क्र.सं.	पूर्व अध्ययन	वर्ष	जल संसाधन आंकलन (बीसीएम)	टिप्पणी
1	प्रथम सिंचाई आयोग	1901-03	1443	रनऑफ गुणांक विधि का उपयोग कर (तत्कालीन बर्मा, असम और पूर्वी बंगाल को छोड़कर)
2	खोसला का सूत्र	1949	1673	इंपेरीकल फार्मूला का उपयोग कर
3	सीडब्ल्यूएंडपीसी	1954-66	1881	प्रवाह डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण + वर्षा-अपवाह (RR) संबंध का उपयोग कर
4	सीडब्ल्यूसी प्रकाशन	1988	1880	भूजल सुधारों सहित
5	सीडब्ल्यूसी	1993	1869	फ्लो डेटा और आरआर संबंध का उपयोग कर
6	राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी)	1999	1953	सीडब्ल्यूसी के 1993 के अध्ययन के आधार पर (ब्रह्मपुत्र और कृष्णा के लिए डेटा संशोधित किया गया था)
7	सीडब्ल्यूसी अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग करते हुए	2019	1999.2	नवीनतम आंकलन

जलाशय निगरानी

सीडब्ल्यूसी देश के 130 जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति की निगरानी करता है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक जलाशय बुलेटिन जारी करता है। उपरोक्त में से 44 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है। इन 130 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 174.233 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 67.58% है।

दिनांक 29.04.2021 के बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज 58.55 बीसीएम था जो इन जलाशयों की लाइव स्टोरेज क्षमता का लगभग 34% है। हालांकि, पिछले साल इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज 72.076 बीसीएम था और पिछले दस वर्षों के लाइव स्टोरेज का औसत 48.826 बीसीएम था। इस प्रकार 130 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 81 प्रतिशत और दस वर्ष के औसत संग्रहण का 120 प्रतिशत है।



दीर्घा



डब्ल्यूएमओ हाइड्रोहब परियोजना के तहत आईआईटी रुड़की द्वारा सीडब्ल्यूसी के देवप्रयाग साइट पर लिडार सेंसर की स्थापना



भारत का अमृत महोत्सव के तहत: 13.04.2021 को यूकेएसडी मिराज, केजीबीओ, सीडब्ल्यूसी हैदराबाद द्वारा भारत @75-जलियांवाला बाग नरसंहार स्मारक दिवस समारोह



मुख्य अभियंता, बराक और अन्य बेसिन संगठन, सीडब्ल्यूसी के नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकारियों की क्षेत्रीय टीम ने लोंगलेंग और जुन्हेंबोटो की यात्रा से पहले 19.04.2021 को कोहिमा में सचिव पीएचई, नागालैंड से मुलाकात की

पोलावरम परियोजना- प्रगति



हाइड्रोलिक सिलेंडर की स्थापना



रेडियल गेट के निचले क्षैतिज गार्डर की स्थापना



8973
70212
14x4 m
n
21 11:00

अपस्ट्रीम कॉफ़र डैम-फ़िल्टर्स और कोर का प्लेसमेंट

शोक सन्देश

अत्यंत दुःख के साथ हमारे पाठकों को सूचित किया जाता है कि श्री जितेंद्र पंवार, निदेशक, सीडब्ल्यूसी एवं श्री एल. कोडंदरामास्वामी, उप निदेशक, सीडब्ल्यूसी का निधन हो गया है। दोनों अधिकारी बेंगलुरु में तैनात थे। कर्नाटक में परियोजना की निगरानी यात्रा से लौटते समय 01.04.2021 को दुखद दुर्घटना का सामना करना पड़ा।

श्री जितेंद्र पंवार 19.10.2000 को सीडब्ल्यूईएस समूह ए में सीडब्ल्यूसी में सहायक निदेशक के रूप में शामिल हुए। अपनी प्रारंभिक सेवा के दौरान वे सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े रहे। एक कार्यकारी अभियंता के रूप में, वह आठ पश्चिम को बहने वाली नदियों (तापी, निचली नर्मदा, किम, दमन, गंगा, अंबिका, पूर्णा, वैतरणा धधर) के जल वैज्ञानिक प्रेक्षण, मौसम संबंधी प्रेक्षण, बाढ़ पूर्वानुमान आदि में शामिल थे। सीडब्ल्यूसी की सभी स्कंधों में सेवा देने के अलावा, उन्होंने सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एसएससीएसी) में भी काम किया।

श्री एल. कोडंदरामास्वामी 01.12.1993 को डिजाइन सहायक के रूप में सीडब्ल्यूसी में सेवा शुरू की और गंगा और सिंधु नदी घाटियों में प्रमुख जल संसाधन परियोजनाओं की योजना और डिजाइन से संबंधित जल उपलब्धता, डिजाइन बाढ़ और जलाशय अवसादन

इतिहास-सर आर्थर कॉटन

15.05.1803 को जन्मे सर आर्थर कॉटन ने पूरे ब्रिटिश भारत में सिंचाई और नेविगेशन नहरों के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने दोलेश्वरम बैराज (राजमहेंद्रवरम), प्रकाशम बैराज और कुरनूल कडप्पा नहर (के.सी. नहर) के निर्माण में बहुत योगदान दिया। के.सी. नहर दो प्रमुख जिलों यानी कुरनूल जिले और कडप्पा जिले को जोड़ती है। के.सी. नहर 150 साल पुरानी प्रमुख सिंचाई प्रणाली है जो कुरनूल जिले के सनकेसुला गांव के पास तुंगभद्रा नदी पर निर्मित एनीकट के दाहिने किनारे से निकलती है। तुंगभद्रा नदी पर सनकेसुला बैराज आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के सनकेसुला गांव के पास कुरनूल शहर से 30 किमी दूर स्थित है। नहर प्रणाली का निर्माण वर्ष 1863 में किया गया था और 1870 तक पूरा हो गया था। इसकी कुल लंबाई 305.65 किमी है जो कुरनूल जिले में सनकेसुला एनीकट से 234.64 किमी तक और कडप्पा जिले में 71.01 किमी कीलंबाई तक फैला है।

दोलेश्वरम बैराज एक सिंचाई संरचना है जिसे 1850 में गोदावरी नदी के निचले हिस्से पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बनाया गया था। इसे 1970 में फिर से बनाया गया और इसका नाम बदलकर सर आर्थर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने मूल निर्माण किया था।



स्वर्गीय श्री एल. कोडंदरामास्वामी, उप निदेशक एवं स्वर्गीय श्री जितेंद्र पंवार, निदेशक, कवासी (बाएं से दक्षिण)

अध्ययन जैसे हाइड्रोलॉजिकल विश्लेषण में शामिल थे। फील्ड सेटअप में, उन्होंने भीमा सब डिवीजन में सहायक अभियंता के रूप में काम किया और ऊपरी कृष्णा सब डिवीजन III, मानगांव के कार्यों को भी संभाला। वह मुख्यालय स्तर और क्षेत्र स्तर दोनों पर पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं की निगरानी से भी जुड़े थे।

सीडब्ल्यूसी ने अपने कर्तव्य के क्रम में अपने दो प्रिय समर्पित अधिकारियों को खो दिया है। पूरा संगठन उनके दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता है और अपूरणीय क्षति के लिए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।



केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध
कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री दीपक कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी-सी)- सदस्य
- श्री के.वी. प्रसाद, निदेशक(जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
- श्री अर्जुन कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केंद्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in

